महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा

प्रैस कतरनें

दिनांक 2 SEP 2021

पंजाब केसरी

'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 'आस' का लोकार्पण'

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य : खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 'आस' का लोकार्पण करते हुए। (संजय कुर्ल)

चंडीगढ़, 1 सितम्बर (बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूचना प्रौद्योगिकी को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा कि आज के दौर में आई.टी. की सही परिभाषा इमिजिएट ट्रांसफॉर्मेशन यानी तुरंत बदलाव है। उन्होंने कहा कि हमें हैपिनैस इंडैक्स की तरफ कदम बढ़ाने हैं। आई.टी. का इस्तेमाल करके 'ईज ऑफ लिविंग' अर्थात प्रदेश के आम आदमी के जीवन में सरलता लाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाए गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 'आस' के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे।

P3

खट्टर ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से यह सॉफ्टवेयर लांच किया गया है। यह सरकारी सेवाओं की समयबद्ध तरीके से डिलीवरी में मील का पत्थर साबित होगा। इसके शुरू होने से लोगों को एक आस बंधी है और हमें इस आस को असल तक लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि लोगों की यह आस तभी पूरी हो सकती है, जब सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए।

खट्टर ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समयसीमा में काम नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेवा डिलीवरी में कोताही बरतने पर आयोग द्वारा तय की गई सजा पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले काम कर देते हैं, उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी सुशासन दिवस को लगभग 4 माह बाकी हैं, इस दौरान हर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

खट्टर ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अभी इसके बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है। इसलिए अभियान चलाकर लोगों को यह बताने की जरूरत है कि उनकी समस्या का समाधान घर बैठे भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय 31 विभागों के 38 संगठनों की 546 अधिसूचित सेवाओं में से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि बाकी सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन किया जाए।

उन्होंने कहा कि 26 अक्तूबर 2014 को जब मैंने जनसेवा का दायित्व संभाला था, उस समय मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के घर व दफ्तर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती थी। उन्हें हर छोटे-बड़े काम के लिए प्रदेश की राजधानी आना पड़ता था। आजाद भारत में मुझे यह सब देखकर बड़ी पीड़ा होती थी और अक्सर सोचता था कि क्यों न लोगों के काम घर बैठे हों, उन्हें अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

'सी.एम. विंडो लांच करके आम आदमी को घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार दिया'

कार्यभार संभालने के मात्र डेढ़ माह के भीतर मौजूदा सरकार ने सी.एम. विंडो लांच करके आम आदमी को घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार दिया। अब तक इस पर लगभग 9 लाख शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से सवा 8 लाख शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। इस तरह देखा जाए तो हर रोज तकरीबन 400 लोगों को अपने छोटे-बड़े कामों के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था। सी.एम. विंडो के चलते इन लोगों के समय और पैसे की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल, वैब हैलरिस, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा जैसी अनूठी पहलों से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। इस मौके पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता और आयुक्त हरदीप कुमार ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग ने विभाग द्वारा की गई आई.टी. पहलों के बारे में अवगत करवाया। विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिव और जिलों के उपायुक्त कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े।